

हिन्दी साप्ताहिक

हर पल निगाहें

Website: www.harpalnigahein.com

RNI. No.: UPHIN/2010/32333

वर्ष-15, अंक: 38

हरचंदपुर-रायबरेली, शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024

(हिन्दी साप्ताहिक)

डाक पंजीयन संख्या RBL/NP-68

पृष्ठ-4,

मूल्य- 1 रुपया

संक्षिप्त....

इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर राज्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब के बारे में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इस फैसले में नौ जोनों की संविधान पीठ ने 8.1 के बहुमत से यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में दिए गए एक पुराने फैसले को पलट दिया। उस समय की 7 जोनों की पीठ ने कहा था कि औद्योगिक अल्कोहल को राज्य सरकारों नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन अब की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक अल्कोहल, भले ही नौ जोनों के लिए न हो, फिर भी इसे नौ जोनों पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्यों को औद्योगिक शराब को रेग्यूलैट करने और उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है।

पूर्ववर्ती सरकारों के समय योग्यता से नहीं, पहुंच और रिश्वत से नौकरी मिलती थी: योगी

-संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि ऊंची पहुंच और रिश्वत से ही मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद से चयन प्रक्रिया को भेदभाव मुक्त बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारिया (समाज कल्याण) और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों समेत कुल 1,950 युवाओं को नियुक्ति प्रदान किया। इस दौरान सीम योगी ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साझा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हाहाआप में से कुछ अध्यर्थियों ने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। सक्षम व समर्थ सात-साढ़े सात वर्ष में चयन प्रक्रिया होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चयन

नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपके पास पहुंच और अभिभावक के पास इतना

में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ।

इसके लिए 2017 में ही तय किया गया कि जितने भी आयोग तथा बोर्ड

योग्यता से नहीं नियुक्ति मिली है, उत्तर प्रदेश भारत की नंबर एक अर्थव्यवस्था और भारत 2047 में विकसित तथा आत्मनिर्भर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने दावा किया, हाहाउनकी सरकार ने अपने पिछले साढ़े छह-

आधार पर नियुक्तियां ईमानदारी से

बढ़ी हो उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से

दौड़ा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने

उम्मीद जताई कि नवचयनित

अध्यर्थियों को जितनी निष्पक्षता और

पारदर्शिता से नियुक्ति मिली है, पूरा

कार्यकाल उत्तीर्ण निष्पक्षता और पारदर्शी

तरीके से बढ़ता जाएगा। ऐसा होने से

उत्तर प्रदेश भारत की नंबर एक

अर्थव्यवस्था और भारत 2047 में

विकसित तथा आत्मनिर्भर बनेगा।

मुख्यमंत्री में दावा किया, हाहाउनकी

सरकार ने अपने पिछले साढ़े छह-

सात वर्ष के कार्यकाल में लगभग

सात लाख युवाओं को सरकारी

नौकरियां दीं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा

का बेहतर माहौल देने के कारण

निजी क्षेत्र में भी लाखों नौजवानों के

लिए नौकरी की संभावना बढ़ाई गई

है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा

पहले नौकरी-रोजगार के लिए देश-

दुनिया में भटकता था।

अतीक अहमद के बेटे उमर को मिली जमानत, लखनऊ सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई

-एजेंसी

लखनऊ। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ

समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय

पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट,

धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश

समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय

एजेंसी के बाद जमानत दे दी है। हालांकि, अपील उमर जेल

में ही रहेगा। क्योंकि उसे दूसरे

मामलों में जमानत नहीं मिली

है। उमर अहमद पर मुकदमे

में सहयोग नहीं करने का आरोप

था। दोनों पर 364 ए के तहत

भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में

मृत्युदंड के बाद कोर्ट के समक्ष

आत्मसमर्पण किया था। 26 दिसंबर

2018 में अतीक अहमद यूपी की

देवरिया जेल में बंद था। मोहित

जायसवाल नाम के व्यापारी को

अतीक अहमद ने लखनऊ से उड़कर

देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके

साथ आपराधिक धारा की गई और 45 करोड़

रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन

कराए गए थे। अतीक और उमर

हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत

भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में

मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान

है। उमर को विशेष कोर्ट के समक्ष

आत्मसमर्पण किया था।

26 दिसंबर

2018 में अतीक अहमद यूपी की

देवरिया जेल में बंद था। मोहित

जायसवाल नाम के व्यापारी को

अतीक अहमद ने लखनऊ से उड़कर

देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके

साथ आपराधिक धारा की गई और 45 करोड़

रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन

कराए गए थे। अतीक और उमर

हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत

भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में

मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान

है। उमर को विशेष कोर्ट के समक्ष

आत्मसमर्पण किया था।

26 दिसंबर

2018 में अतीक अहमद यूपी की

देवरिया जेल में बंद था। मोहित

जायसवाल नाम के व्यापारी को

अतीक अहमद ने लखनऊ से उड़कर

देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके

साथ आपराधिक धारा की गई और 45 करोड़

रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन

कराए गए थे। अतीक और उमर

हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत

भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में

मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान

है। उमर को विशेष कोर्ट के समक्ष

आत्मसमर्पण किया था।

26 दिसंबर

2018 में अतीक अहमद यूपी की

देवरिया जेल में बंद था। मोहित

जायसवाल नाम के व्यापारी को

अतीक अहमद ने लखनऊ से उड़कर

देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके

साथ आपराधिक धारा की गई और 45 करोड़

रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन

कराए गए थे। अतीक और उमर

हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत

भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में

सम्पादकीय

धान की पीड़ा

पंजाब में धान की भरपूर पैदावार के बाद किसानों का हैरान-परेशान होना व्यवस्था की विसंगतियों व तंत्र की नाकामी को ही दर्शाता है। राज्य की अनाज मँडियों में धान बहुतायत में पड़ा होना न केवल खरीद एजेंसियों की अक्षमता को दर्शाता है बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों में व्यावहारिक तालमेल न होना भी बताता है। जिसके चलते विपणन से जुड़े हितधारक विरोध जता रहे हैं। विडंबना देखिए कि किसान खून-पसीने से उगायी फसल को भी समय पर नहीं बेच पाने से परेशान हैं। किसान धीमी खरीद प्रणाली से चिंतित हैं। वहीं चावल मिल मालिकों की दलील है कि उनके पास अतिरिक्त भंडारण की क्षमता नहीं है। दूसरी ओर धान की खरीद से जुड़े आढ़ती अपने कमीशन को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हालात किसानों को परेशान करते हैं और खरीद प्रणाली में सुधार की जरूरत को बताते हैं। विडंबना है कि यह सारा हंगामा एक ऐसी फसल को लेकर हो रहा है, जिसको उगाने में प्रयुक्त पानी ने राज्य में एक गंभीर जल संकट को जन्म दे दिया है। वजह है धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिये भूजल का अंधाधुंध दोहन। फलतरु राज्य का एक बड़ा इलाका मरुस्थलीकरण की ओर उन्मुख है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि पंजाब आखिर कब तक धान की खेती के जरिये अपने इन अनमोल प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करता रहेगा? इसमें दो राय नहीं हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद पंजाब के धान उत्पादकों को केंद्रीय पूल में अधिक अनाज के योगदान के लिये प्रेरित करती रही है। निस्संदेह, हरित क्रांति के बाद देश की खाद्य सुरक्षा शृंखला को मजबूत बनाने में पंजाब का बड़ा योगदान रहा है। जिसके चलते देश खाद्यान्न संकट व कुपोषण के अभिशाप से किसी हद तक मुक्त हो सका है। जबकि एक हकीकत यह भी है कि यह फसल पंजाब का मुख्य भोजन नहीं रही है निश्चित तौर पर केंद्र व राज्य सरकार को तालमेल बनाकर इस संकट के समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लबालब भरे अन्न भंडार राज्य की अपेक्षाओं और केंद्र की आवश्यकताओं के बीच तालमेल के अभाव को दर्शाते हैं। विडंबना देखिये, इसी धान के उत्पादन का एक प्रतिप्रभाव यह भी है कि पंजाब के हिस्से में प्रदूषण बढ़ाने वाला पराली दहन का आक्षेप आता है। जिसे उत्तर क्षेत्र में अकूबर-नवंबर में बढ़ाने वाले वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक बताया जाता रहा है। जबकि हकीकत यह है कि एक तो किसानों को पराली निस्तारण का कारगर विकल्प केंद्र व राज्य सरकारें नहीं दे पायी हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों के पास रबी की फसलों की बुआई के लिये अधिक समय नहीं बचा होता।

जब नए-नए प्रयोग करने शुरू किए थे, तब करवा चौथ के मौके पर किसी चौनल ने ब्रत करने वाली महिलाओं के लिए चांद की लाइव तस्वीरें दिखाई थीं। उसके बाद यह सिलसिला मैदान में उतरे बाकी चौनलों ने भी शुरू कर दिया। उस समय पत्रकारिता और मीडिया का ऐसा हाल देखकर आश्वर्य हुआ था कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें पूजा, ब्रत जैसी निहायत व्यक्तिगत बातें भी अब खबरों के कारोबार में इस्तेमाल हो रही हैं। उस दौर में एनडीए की सरकार थी। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवानी की प्रधानमंत्री बनने की हसरत थी और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ भाजपा को यकीन था कि भारत को चमकाने के नाम पर उसकी सियासत में चार चांद जरूर लगेंगे। बहरहाल, ऐसा नहीं हुआ, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। तब कांग्रेस के नेतृत्व में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, भोजन का अधिकार जैसे कई जनहितकारी फैसले भी आए। लेकिन अपने 10 सालों की सत्ता में कांग्रेस मीडिया के जारी समाज में जहर भरने के दबे-छिपे एंजेंडे को रोक पाने में नाकाम रही, बल्कि यह कहा जाए कि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि उसकी नाक के नीचे दक्षिणपंथी ताकतें कैसा खेल कर रही हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। कांग्रेस की इस नासमझी, नाकामयाबी और नजरंदाजी का खामियाजा अब देश भुगत रहा है। क्योंकि अब न्यूज चौनल करवा चौथ पर केवल चांद

हिंद-प्रशांत इलाके में भारतीय कूटनीतिक बढ़त

A photograph showing four world leaders in formal attire: Narendra Modi (India), Vladimir Putin (Russia), and Xi Jinping (China) standing together. Narendra Modi is on the left, wearing a dark suit and white shirt. Vladimir Putin is in the center, wearing a dark suit and red tie. Xi Jinping is on the right, wearing a blue suit and red tie. Another man in a white shirt and glasses is partially visible on the far left. They appear to be at a formal international event.



के इश्यू पर जस्टिन ट्रूडो जैसी शब्दियत की तरफदारी करें, तो नई दिल्ली को पाला बदलने में कितनी देर लगेगी? दरअसल, यही हुआ है। शी, ताइवान के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और सैन्यीकरण चीन कर रहा है। चीन ने कंबोडिया में एक विस्तारित नौसैनिक बंदरगाह पर भी काम शुरू किया है, जो किसी अन्य एशियाई देश में उसका पहला सैन्य अड्डा बन सकता है। सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौता, इसी तरह की कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है। पेड़चिंग, अन्य पश्चांत देशों को मोर्चा खोल दिया। यूक्रेन को 54 अरब डालर की प्रतिबद्धता अमेरिकी टैक्स पेयर्स को चुभने लगी है। अमेरिकी अधिकारी इस बात से जूझ रहे हैं, कि एक ही समय में चीन और रूस से कैसे निपटें? जो आमतौर पर जेरे बहस नहीं होती, वो हैं पुतिन की खामोश चालें। हिन्द-प्रशांत समेत दक्षिण-पश्चिम एशिया में जो रणनीतिक बदलाव आ रहा है, उसमें ह्यामास्को-पेड़चिंग नेक्सस्ल की बड़ी भूमिका है। पुतिन और शी यदि प्रच्छन्न हैं, तो मोदी बिलकुल प्रत्यक्ष रूप से कूटनीति के अखाड़े में हैं। पुतिन और शी ने दक्षिण-पूर्व से लेकर पश्चिम एशिया में व्यापक

नहीं दिखा रहे, मेंहदी जिहाद के एजेंडे को भी चला रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से किस्म-किस्म के जिहाद देश में बताए जाने लगे हैं। ताजा मामला करवा चौथ पर लगाए जाने वाली मेंहदी से जुड़ा है। इस त्यौहार के मौके पर शहरों के व्यस्त बाजारों में फुटपाथ पर मेहंदी लगाने और लगावाने वालों की भीड़ आम बात है, कई सालों से ऐसा सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बार उपर में कुछ जगहों पर दुगार्वाहिनी संगठन या इसी तरह के हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐलान किया कि हिंदुओं के इस धर्म में मेंहदी लगाने का काम मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो भी वायरल हुआ, जो भरे बाजार में मुस्लिम लड़कियों को मेंहदी लगाने से रोक रहा था और गुंडागर्दी कर रहा था। इस तरह की खबरों को अगर प्रचारित-प्रसारित न किया जाए, तो ऐसे पागलपन को बहाँ दबाया जा सकता है, लेकिन अगर मकसद पूरे देश को धर्मांधता के पागलखाने में तब्दील करना ही हो तो मीडिया की सेवाएं ती जाती हैं। इसलिए करवा चौथ पर चांद और पति की लंबी आयु के लिए पूजा करने वाली सुहागिनों की तरस्वीरों, फिल्मी सितारों की करवा चौथ वाली पूजा के वीडियो के साथ-साथ अब मेंहदी जिहाद पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। हिंदू-मुसलमान के नाम पर दिन-रात बहसें कराकर अच्छे-भले लोगों का रक्तचाप बढ़ाने वाले एंकर संघ और भाजपा के एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं। इस पागलपन में देश के एक बड़े तबके को शिकार बनाया जा रहा है, जिसके रोज नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के जलम में उपर के बहुगुण्डा में दंगा भड़का जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। इसमें भी गलत खबरों को धड़ल्ले से प्रसारित किया गया। उस युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में झूठी बातें फैलाई गईं और इसमें कई बड़े पत्रकारों और भाजपा नेताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि बहराइच पुलिस ने साफ कहा कि



A vibrant Rangoli design featuring a large central flower with a glowing center, surrounded by colorful petals and leaves, with small lit candles (diyas) placed around it.

प्रियंका की चुनावी सियासत का आगाज

अपने बड़े भाई राहुल गांधी की केरल के वायनाड की छोड़ी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिये प्रियंका गांधी-वाड़ा ने बुधवार को परचा भरकर अपनी चुनावी राजनीति की शुरूआत कर दी है। परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक और हमले का अवसर देते हुए कांग्रेस ने प्रियंका को मैदान में उतारा तो है, लेकिन राजनीतिक विश्वेषक प्रियंका का पलड़ा इस कदर भारी बतला रहे हैं कि भारतीय संसद पहली बार एक नहीं, दो नहीं बल्कि गांधी-नेहरू परिवार के तीन सदस्यों को एक साथ देखने जा रही है। राहुल ने 2024 का आम चुनाव वायनाड के साथ रायबरेली से लड़ा था। दोनों सीटों पर जीतने के बाद उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी जहां से वे 2019 में भी निर्वाचित हुए थे। उस बार भी वे दो जगहों से चुनाव लड़े थे। दूसरा लोकसभा क्षेत्र अमेठी था, जहां उन्हें स्मृति ईरानी ने हराया था। 1998 से रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही उनकी मां सोनिया गांधी इस साल हुए चुनाव में खड़ी नहीं हुई परन्तु उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। यदि वायनाड में होने जा रहे उपचुनाव में प्रियंका जीत जाती हैं तो वे परिवार की तीसरी मौजूदा सांसद होंगी।

वे बेशक गांधी परिवार की सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से चुनावी प्रबंधन में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी प्रियंका सड़कों पर संघर्ष करना जानती है, विमर्श रचती हैं, भाजपा के आरोपों का मुहंतोड़ जवाब देती हैं और मुद्दों को लेकर सरकार पर टूट पड़ती हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान पार्टी की बतौर महासचिव उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिम्मा सम्हाला। हालांकि 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को बहुत सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके कारण काफी लोगों को लगने लगा था कि प्रियंका में वह बात नहीं है जिसकी उम्मीद थी। भाजपा के लिये यह विशेष संतोष की बात थी। नाकामी से विचलित हुए बिना प्रियंका ने अपनी लड़ाई का मुंह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ महिला सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर वे मुखर हर्हीं। उपर में श्वेती हूं, लड़ सकती हूश का नारा चाहे विशेष कामयाब न हो पाया परन्तु उन्होंने प्रदेश में होने वाले बलात्कारों तथा उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार आवाजें उठाईं। प्रशासन ने कई जगहों पर उन्हें जाने से रोकने की कोशिशें की थीं, पर वे हाथरस, उन्नाव आदि गयीं और अपनी कटिबद्धता व साहस का परिचय देती रहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें राजनीतिक समझ उनके पिता राजीव गांधी की तरह सक्रिय राजनीति में उत्तरने के बाद हुई। जब राजीव प्रधानमंत्री बने तो वे बहुत छोटी उम्र में उनके साथ पिता के चुनावी क्षेत्र अमेठी जाया करती थीं। उनके परिवार के प्रति लोगों के अनुराग को उन्होंने नजदीक से देखा था और उनमें देश के प्रति दायित्व की समझ कम उम्र में विकसित हो गयी थी। उन्होंने अपने भाई के साथ-साथ पहले दादी इंदिरा गांधी और बाद में राजीव की शहादत को भी देखा था। निराशा व नाराजगी के बावजूद उन्होंने देश के लिये परिवार के इन दो लोगों के त्याग का महत्व समझा। देश के प्रथम राजनीतिक परिवार की सदस्य होने के नाते सियासत का प्रशिक्षण उन्हें स्वाभाविकतः बचपन से ही मिलता गया। इसका लाभ लेते और उसका प्रदर्शन करते हुए प्रियंका लगातार सक्रिय रहीं। कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी को कहीं सफलता मिली तो कहीं असफलता, लेकिन उनके करिशमाई व्यक्तित्व के ज्यादातर लोग मुरीद होते गये। मौजूदा लोकसभा में यदि कांग्रेस की सदस्य संख्या लगभग दोगुनी हुई है तो उसमें राहुल एवं कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ प्रियंका के भी योगदान से कोई इंकार नहीं कर सकता। वैसे प्रियंका का चुनावी प्रबन्धन का 35 वर्षों का अनुभव है- कभी अपनी मां सोनिया तो कभी गहल के लिये। इस बार उन्होंने अपेक्षा में किंशोरीलाल शर्मा को जीत लिलाई थी।

पिछले दिनों राहुल द्वारा की गयी दो पदयात्राओं के दौरान जो विमर्श गढ़ा गया तथा जिसे लोकसभा में सांसद के तौर पर स्वयं राहुल व कांग्रेस ने बढ़ाया, उसे सड़कों पर प्रियंका ने मजबूती दी। राहुल जिस प्रकार महाराष्ट्र, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय आदि की बातें उठाते रहे, उसमें अपना सशक्त स्वर प्रियंका ने मिलाया है। मोदी सरकार तथा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी बेखौफ होकर प्रियंका ने

